आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 02.05.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह सात बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा–अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले।
- प्रदेश में सशक्त भू–कानून लागू, राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, पर हस्ताक्षर किये।
- देश में अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह साढे 12 प्रतिशत से अधिक बढ़कर दो लाख 37 हजार करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा।
- पौड़ी में वनाग्नि रोकथाम अभियान में जिलाधिकारी हुए शामिल, जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ रांसी मैदान के समीप लगभग 270 किलोग्राम से अधिक पिरुल किया एकत्रित।

केदारनाथ कपाट

विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह सात बजे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा–अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिये खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर देश–विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए धाम पहुंचे, जहां भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला।

कपाट उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया, जिसने मंदिर परिसर की दिव्यता और भव्यता को और अधिक बढ़ा दिया।

बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली 27 अप्रैल को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से विधिपूर्वक प्रस्थान कर गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड होते हुए कल शाम केदारनाथ धाम पहुंची। यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा डोली का भव्य स्वागत किया गया। पुष्पवर्षा, भजन–कीर्तन और जयकारों के साथ डोली का अभिनंदन किया गया।

आज प्रातः, पूरी विधि–विधान और मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस पावन क्षण पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कपाट खुलते ही केदारघाटी ''हर हर महादेव'' और ''जय बाबा केदार'' के नारों से गूंज उठी, और वातावरण में गहन भक्ति व आस्था की अनुभूति हुई।

इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, आपदा राहत टीमें, चिकित्सकीय स्टाफ और स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गौरतलब है कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले जा चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।

भू–कानून लागू

प्रदेश में सशक्त भू–कानून लागू हो गया है। भूमि प्रबंधन और भू–व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू–कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्यपाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू–अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में जनसांख्यिकीय बदलाव की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी।

विधेयक में हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के शेष 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए राज्य के बाहर से व्यक्ति के भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है। इन जिलों में उद्योग और अन्य उपयोग के लिए खरीदी जाने वाली भूमि का निर्धारित से अन्य प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बाहरी व्यक्ति आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्गमीटर भूमि खरीद सकेंगे, लेकिन खरीद की अनुमति परिवार के अन्य व्यक्तियों को नहीं मिलेगी। इस संबंध में भूमि क्रेता को शपथ पत्र देना होगा। भू–कानून के प्रविधान का उल्लंघन होने पर भूमि सरकार में निहित होगी। विधेयक के प्रविधानके अनुसार भूमि खरीद की अनुमति अब जिलाधिकारी नहीं देंगे। शासन स्तर से ही यह अनुमति दी जाएगी।

कार्रवाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नगर निगम हरिद्वार की ओर से सराय स्थित भूमि को क्रय किये जाने के प्रकरण में दोषी पाए गए अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में चार अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। एक कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं, जबकि एक अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

सांसद स्वच्छता अभियान

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचलेश्वर मंदिर घाट पर गंगा की सहायक नदी बाणगंगा के तट पर स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण और जन–जागरूकता का संदेश दिया। इस अभियान में न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। श्री रावत ने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियां हमारी आस्था और जीवन

का आधार हैं। इन्हें स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। यह अभियान केवल सफाई का नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण सौंपने का संकल्प है।

जीएसटी संग्रह

वस्तु और सेवा कर– जीएसटी संग्रह में अप्रैल माह के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12 दशमलव छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह अब तक के सबसे अधिक दो लाख 37 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया। केंद्रीय जीएसटी संग्रह इसी माह के दौरान बढ़कर 48 हजार 634 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी बढ़कर 59 हजार 372 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

पिरूल ब्रिकेट

पौड़ी के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ रांसी मैदान के पास एक बार फिर पिरूल के संकलन का अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 270 किलो से अधिक पिरुल एकत्रित किया गया। जिलाधिकारी के दिशा–निर्देशन में पिरूल एकत्रीकरण को लेकर विकासखण्ड स्तर चलाये गये अभियानों में अब तक 75 कुन्तल से अधिक पिरुल एकत्रित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीडाण्डा विकासखण्ड के अन्तर्गत पिरूल एकत्रीकरण को लेकर क्लस्टर लेवल फेडरेशन अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे लगातार पिरूल एकत्र कर ब्रिकेटिंग यूनिट तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिरूल उद्योगों के लिए बायोमास का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि पिरुल की व्यवस्थित तरीके से प्रोसेसिंग कर ब्रिकेट तैयार करने के लिए सतपुली में एक बड़े प्लांट की स्थापना की जायेगी। एक आधुनिक व वृहद् स्तर के पिरुल प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए नैनीडाण्डा के सीएलएफ व बीडीओ को रिसोर्स पर्सन बनाया जा रहा है।

गौरतलब है कि थर्मल पावर उत्पादन प्लांट व फोर्ज का उपयोग करने वाले उद्योगों में कोयले के साथ 20 प्रतिशत मात्रा में बायोमास का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से बायोमास ईंधन के रूप में पिरूल से बनी ब्रिकेट की सप्लाई, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर खोलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नई पहल की है।

चयन प्रक्रिया पूरी

टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। योजना में 200 युवाओं का चयन हुआ है। योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न आयु वर्ग के युवाओं की प्रतिभाओं को चयनित कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।